

माध्यमिक शिक्षा: गुणवत्ता, चुनौतियाँ और सभांवनाएं

सारांश

स्वतन्त्रता प्राप्त होते ही हमारे राष्ट्र ने प्रारंभिक शिक्षा के प्रचार व प्रसार का जो वीणा उठाया व सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं के अथव प्रयत्नों से आज प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने के करीब पहुँच चुका है। तत्पश्चात माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश लेने वाले छात्रों की संख्या में बेतहासा बढ़ि हुई है जिसको स्वीकार करना एक चुनौती व आवश्यकता बन चुकी है। माध्यमिक शिक्षा का विकास इसाई मिशनरियों के द्वारा प्रारम्भ किया गया। माध्यमिक शिक्षा प्राथमिक व उच्च शिक्षा की कड़ी के साथ-2 ही अति महत्वपूर्ण अंग है जिसकी उन्नति के बांग सम्पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को सुधारना सम्भव ही नहीं है। इसकी गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए कई चुनौतियाँ हैं जिसका सामना करना है इस लेख में माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के साथ ही साथ गुणात्मक सुधार तथा व्यावसायीकरण पर प्रकाश डाला गया है।

मुख्य शब्द : जनशक्ति, रोजगारोन्मुख, लोकतान्त्रिक।

प्रस्तावना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने स्पष्ट किया कि—“एक निश्चित स्तर तक बिना किसी भेदभाव के सभी को समान शिक्षा उपलब्ध हो को वरीयता दी जानी चाहिए, साथ ही पूरे देश में समान शिक्षा सरचंना 10+2+3 लागू होनी चाहिए, इसमें प्रथम 10 वर्षीय शिक्षा की ऐसी आधारभूत पाठ्यचर्या तैयार होनी चाहिए जिसके द्वारा राष्ट्रीय मूल्यों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हो सके। साथ ही प्रत्येक स्तर की शिक्षा का न्यूनतम अधिगम स्तर (Minimum level of learning) निश्चित होना चाहिए और उसमें गुणात्मक सुधार होना चाहिए। माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की विषमताओं को दूर किया जाना चाहिए और महिलाओं अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलागों और प्रौढ़ों की शिक्षा के लिए विशेष प्रयत्न किये जाने चाहिए।

शिक्षा को जीवन की प्रयोगशाला कहा गया है। शिक्षा एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को संस्कारी व उत्कृष्ट व्यक्ति बनाने में मदद करती है। प्रत्येक व्यक्ति को समाज की सर्वोच्चता प्राप्ति के लिए गुणात्मक शिक्षा की अति आवश्यकता होती है। किन्तु वर्तमान शिक्षा प्रणाली नागरिक निर्माण व राष्ट्र निर्माण से अति दूर होती जा रही है। केवल सूचनाओं व सिद्धान्तों तक ही सीमित रह गयी है। जब तक सभी शिक्षाओं का आपसी सामजिक सही नहीं होगा तब तक शिक्षा के लिए कोई भी उपयुक्त कदम उठाना सभव नहीं होगा।

प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा सभी में आपसी तालमेल बेहतर होना चाहिए जहाँ एक तरफ प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण व उच्च शिक्षा का वैश्वीकरण हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा उच्च शिक्षा के आधार तैयार करती है। यदि माध्यमिक शिक्षा कमजोर होगी तो उच्च शिक्षा रूपी भवन कभी भी मजबूत नहीं हो सकेगा। वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी, उपेक्षित व दोयम दर्जे की साबित हो रही है। यदि राष्ट्र को उन्नति व विकास के मार्ग पर ले जाना है तो माध्यमिक शिक्षा को उपयोगी, व्यावसायिक रोजगारोन्मुख, सशक्त बनाया जाना अति आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षा को एक पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करना, जनशक्ति के विकास का आधार, बच्चों के विकास का आधार, नागरिकता की शिक्षा व अधिकांश व्यक्तियों के लिए पूर्ण शिक्षा है जिसके महत्व को शिक्षा से जुड़े सभी व्यक्तियों, संस्थाओं व पहलुओं को समझना होगा।

अध्ययन का उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952 (मुदालियर आयोग) ने माध्यमिक शिक्षा के चार उद्देश्य निश्चित किए—

1. लोकतान्त्रिक नागरिकता का विकास



दिनेश प्रताप सिंह
प्रवक्ता,
शिक्षाशास्त्र विभाग,
आई0एम0आर0,
गाजियाबाद

2. व्यक्तिव का सर्वांगीण विकास
3. व्यावसायिक कुशलता का विकास
4. नेतृत्व शक्ति का विकास

एन०सी०ई०आर०टी० ने 2000 में विद्यालयी शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा की रूपरेखा प्रस्तुत की उसमें निम्नलिखित उद्देश्य सुनिश्चित किया गया है—

1. बच्चों को अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने व उसके विकास करने में प्रशिक्षित करना।
2. बच्चों को विभिन्न विषयों का ज्ञान कराना, उन्हे सोचने विचारने एवं निर्णय लेने में दक्ष करना।
3. बच्चों का समाजीकरण करना, उन्हे आवश्यक सामाजिक परिवर्तन करने हेतु तैयार करना।
4. बच्चों को देश विदेश की संस्कृतियों का ज्ञान कराना और उनमें सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास करना।
5. बच्चों में सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और लोकतान्त्रिक मूल्यों का विकास करना एवं उसके अनुकूल आचरण व चरित्र विकास करना।
6. बच्चों को उनकी रुचि योग्यता व आवश्यकतानुसार किसी शारीरिक श्रम कार्य को बेझिझक करने की ओर प्रवृत्त करना।
7. बच्चों को लोकतान्त्रिक शासक प्रणाली का ज्ञान कराना व उन्हें लोकतान्त्रिक जीवन शैली में प्रशिक्षित करना।
8. बच्चों को राष्ट्रीय लक्ष्यों— पर्यावरण संरक्षण व जनसंख्या नियंत्रण के लिए जागरूक करना और उनमें वैज्ञानिक प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और अन्तराष्ट्रीय सद्भाव का विकास करना।
9. बच्चों को संसार के मुख्य धर्मों का सामान्य ज्ञान कराना और उनमें धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना।

माध्यमिक शिक्षा की मुख्य चुनौतियाँ

माध्यमिक शिक्षा की बहुत सी चुनौतियाँ हैं उनमें से कुछ मुख्य हैं—

1. कोटारी कमीशन ने सुझाव दिया कि शिक्षा पर आंबटित सम्पूर्ण बजट का 1/3 भाग माध्यमिक शिक्षा पर खर्च हो व 1/3 भाग उच्च पर किन्तु 50: धन प्राथमिक पर खर्च हो रहा है।
2. मार्च 2009 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्ष 2017 तक 15–16 वर्ष आयु वर्ग के शत प्रतिशत बच्चों को कक्षा 9 व 10 तक की शिक्षा उपलब्ध करवाना।
3. वर्ष 2011 में 14–18 आयु वर्ग के लगभग 12.5 करोड़ बच्चों में से लगभग 5.0 करोड़ बच्चे ही माध्यमिक शिक्षा में पंजीकृत है शेष 7.2 करोड़ बच्चे अभी भी माध्यमिक शिक्षा से बाहर हैं।
4. सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में सतत मूल्यांकन की प्रक्रिया शीघ्र लागू हो।
5. भारत सरकार ने 1968 से जीडीपी का 6: व्यय करने की घोषणा की है परन्तु अभी भी लगभग 4: ही व्यय किया जा रहा है। सरकार स्वयं ही शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए विशेष चिन्तित नहीं है। बिना पैसे के तो शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन का कार्य किया नहीं जा सकता।

6. माध्यमिक शिक्षा के प्रसार एवं उन्नयन के लिए जो भी सामान्य एवं योजना बजट होता है उसके भी आधे से अधिक धनराशि का बन्दरबॉट हो जाता है।
7. माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा प्रणाली वैध एवं विश्वसनीय नहीं है। अतः छात्रों की योग्यताओं, सृजनात्मकता व जिज्ञासा का समुचित मूल्यांकन नहीं हो पाता है।
8. शिक्षण विधियों एवं पाठ्यक्रम के प्रारूप के कारण छात्रों में सहयोग की भावना, आत्मविश्वास, अनुशासन तथा आज्ञाकारिता जैसे गुणों का विकास समुचित नहीं हो पाना है।
9. विद्यालयों का पाठ्यक्रम, आवश्यकताओं व अभिरुचियों के अनुरूप न हो पाना है।
10. सभी प्रान्तों में अनेक प्रकार के माध्यमिक विद्यालयों का सचांलन जैसे नवोदय विद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, रेलवे विद्यालय, राजकीय विद्यालय व प्रान्तीय विद्यालय, सरकारी व गैर सरकारी विद्यालय, धार्मिक संगठनों द्वारा सचांलित आदि जिनका प्रशासन व विद्यालयी संगठन अति कठिन चुनौती है।
11. माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षण विधि व्याख्यान विधि ही है।
12. माध्यमिक शिक्षा में सृजनात्मकता व जिज्ञासा का पूर्ण अभाव है।
13. माध्यमिक विद्यालयों का मूल्यांकन व परीक्षा सिर्फ छात्रों के सज्जानात्मक पक्ष तक ही सीमित है भावात्मक व कियात्मक पक्ष पूर्णतः उपेक्षित है जिससे छात्रों की निर्णय शक्ति, तर्कशक्ति, कल्पनाशक्ति एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन का अभाव दिखता है।
14. माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक छात्र संबंध एवं अन्तः-क्रिया का अभाव होता जा रहा है। जिससे शिक्षा की गुणवता प्रभावित होती है।
15. माध्यमिक शिक्षा के लिए एक और मुख्य चुनौती अपव्यय व अवरोधन है। जिससे बस्ते का बोझ भी कम किया जा सकेगा।
16. माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण भी एक अति महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका समाधान एक आवश्यक कदम होगा।
17. अनुशासनहीनता की समस्या माध्यमिक स्तर पर एक महत्वपूर्ण चुनौती है जिसका समाधान से माध्यमिक शिक्षा को उन्नति स्तर पर पहुंचायें जा सकता है।
18. माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है।

संभावनाएँ या सुझाव

माध्यमिक शिक्षा की गुणवता में सुधार के बगैर सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था में उन्नयन की बात बेमानी ही होगी। सम्पूर्ण व्यवस्था में सुधार निम्नलिखित बिन्दुओं पर प्रतिबद्धता दिखाकर सार्वभौमिकरण की संस्कृति विकसित कर, चुनौतियों के सन्दर्भ में निम्नलिखित रूप में समाधान के प्रयास किये जा सकते हैं।

1. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को उद्देश्यपूर्ण व सैद्धांतिक के साथ-2 क्रियात्मक भी बनाया जाय तथा 10 वर्षीय आधारभूत पाठ्यचर्चा बनायी जाय।

2. माध्यमिक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था को लचीला बनाया जाना चाहिए क्योंकि राज्य व केन्द्र सरकारें अपने हितों के लिए अपने ही ढंग से तोड़ मरोड़ कर पेश करती रहती है।
3. केन्द्रीय सरकार को शिक्षा बजट को 6: व भविष्य में इसे बढ़ाकर 10: कर दिया जाना चाहिए।
4. माध्यमिक विद्यालयों में बढ़ती छात्रों की संख्या भी एक समस्या बनी हुई है इसका समाधान विद्यालयों में शिक्षा की संख्या को बढ़ाकर किया जा सकता है।
5. माध्यमिक विद्यालयों में परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है इसको सुधार करके 25–35: लघुउत्तरीय व बहुविकल्पीय प्रश्नों को समाहित किया जाना चाहिए जिससे उनके तनाव को कम व उपलब्धियों को बढ़ाया जाना सम्भव हो सके।
6. आदिवासी व पिछड़े इलाकों में जहाँ विद्यालयों का अभाव है वहाँ पर विद्यालयों की स्थापना हेतु विशेष प्रयास किया जाना चाहिए जिससे आदिवासी व पिछड़े इलाकों के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
7. एक और मुख्य समस्या नामांकन की है कहीं—कहीं विद्यालय है छात्र नहीं है। प्रशासनिक अधिकारियों को विद्यालयों को मान्यता प्रदान करते समय ध्यान देना चाहिए कि उस इलाके में कितने विद्यालयों हैं जो मान्यता प्राप्त है। जहाँ विद्यालयों की पर्याप्त संख्या नहीं है वहाँ मान्यता प्रदान करने में स्थिलता रखी जाय।
8. माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक महौल को बेहतर बनाने के लिए विद्यालयों में कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक हो वहाँ खेलकूद एवं साहित्यिक एवं सार्संकृतिक क्रियाओं का आयोजन भी तभी किया जा सकता है जब शिक्षक रुचि ले।
9. प्रत्येक विद्यालय में निर्देशन व परामर्श केन्द्र की स्थापना की जाय जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान सृजनात्मक व क्षमता आधारित किया जाए।
10. माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को ट्यूशन पढ़ाने पर पूर्ण रूप से रोक लगायी जानी चाहिए जिससे वे विद्यालयों में पढ़ाने में रुचि ले सकेंगे।
11. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में हस्त कौशल शिक्षा, बहुउद्देशीय पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के कार्यानुभव तथा समाजोपयोगी उत्पादक कार्य तथा कार्य शिक्षा को शामिल किया जाना चाहिए।
12. माध्यमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, राष्ट्रीय एकीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय अवयोग, मूल्य शिक्षा, पर्यटन शिक्षा तथा उदारीकरण तथा उपभोक्ता शिक्षा के साथ-2 निजीकरण एवं भूमण्डलीयकरण आदि प्रकरणों को शामिल किया जाना चाहिए।
13. माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति एवं विद्यालयी गतिविधियों में अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।
14. बहुउद्देशीय विद्यालयों की स्थापना की नहीं गयी जो की भी गयी वहाँ भ्रष्टाचार व अनियमितता का ही बोल बाला रहा है।

15. व्यावसायिक विद्यालयों में सबसे कठिन समस्या योग्य दक्ष व प्रशिक्षित शिक्षकों की भी कमी है। जिसके अभाव में शिक्षण की उपयुक्त व्यवस्था सम्बंध नहीं है।
16. माध्यमिक विद्यालयों में अनुशासन की समस्या एक प्रमुख समस्या है इसके लिए सरकार, समाज, शिक्षकों अभिभावकों सभी को योगदान देना होगा— गुटखे, बीड़ी, शराब आदि नशीले पदार्थ की दुकानें विद्यालयों के आसपास नहीं स्थापित की जानी चाहिए।
17. अध्यापकों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन सही ढंग से नहीं हो पाना भी एक कमी है जिसका समाधान करके माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को बेहतर किया जा सकता है।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में माध्यमिक शिक्षा अति सकंडमण काल से गुजर रही है। आज इसका उद्देश्य सीमित रह गया है केवल अंक लाने व डिग्री प्राप्त करने तक सीमित रह गयी है। विद्यालयों में शैक्षिक माहौल लुप्त हो रहा है या अपने वास्तविक कार्यों को ही नहीं कर पा रहा है। विद्यालयों में छात्र ज्ञान के लिए लगता है आया ही नहीं अध्यापक भी अपने कर्तव्यों से विमूळ हो रहा है। कोठारी महोदय की कल्पना “भारत के भाय का निर्माण इसकी कक्षाओं में हो रहा है” आज वास्तविक नहीं साबित हो रही है। सामाजिक अवमूल्यन के साथ-2 अध्यापकों व छात्रों की चारित्रिक प्रधानता की कमी के कारण स्वतन्त्रता के पश्चात विद्यालयों की संख्यात्मक वृद्धि तो हुई है किन्तु गुणात्मक वृद्धि कही भी देखने को नहीं मिल पा रही है जिसको अति आवश्यकता है।

प्राथमिक शिक्षा में सर्वशिक्षा अभियान की सफलता के उपरान्त सरकार ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) का शुभारम्भ किया है जिसका मुख्य उद्देश्य माध्यमिक शिक्षा का विस्तार व उसका स्तर सुधारना है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, त्वेऽप्त्वा, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमि करण (USE) का लक्ष्य हासिल करने के लिए भारत सरकार की नवीनतम पहल है।

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने माध्यमिक शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन के लिए कुछ मार्गदर्शन तत्व लागू किये हैं— कहीं से भी पहुँच, सामाजिक न्याय के लिए बराबरी, प्रासारिकता, विकास, पाठ्यक्रम एवं ढाँचोंगत पहलू।

मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अनुसार— सर्वशिक्षा अभियान सफलतापूर्वक लागू होने से बड़ी संख्या में छात्र उच्च प्राथमिक कक्षाओं में बड़ी संख्या में छात्र उच्च प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण हो रहे हैं। तथा माध्यमिक शिक्षा के लिए जबरदस्त मॉग उत्पन्न कर रहे हैं।

यदि सरकार की व्यवस्था दुरुस्त हो तो सभी विद्यालयों में गरीब, दलित व पिछड़े वर्गों के सभी बच्चों को एक साथ एक समान शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। सभी लोगों को स्वार्थपरकता त्यागकर देशहित की बातों को सोचना चाहिए जिससे कार्य धरातल पर दिखाई दे सके। किसी भी क्षेत्र में यदि ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा से

कार्य किया जाये तो कम साधनों से भी अच्छे परिणाम किए जा सकते हैं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. राजपूत, जगमोहन सिंह, 2009, शिक्षा में कौशल की अनदेखी (दैनिक जागरण लखनऊ, पुष्ट -6) सिंह, कर्ण, 2009, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास, लखीमपुर खीरी, गोविन्द प्रकाशन।
2. पाठक, पीठी०, 2005, भारत शिक्षा और उसकी विशेषताएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
3. त्यागी, गुरुशरण दास, 2002, भारत में शिक्षा का विकास, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।
4. लाल, रमनबिहारी, 2010, भारतीय शिक्षा का इतिहास: विकास एवं समस्याएँ, आर० लाल बुक, मेरठ एन०सी०इ०आर०टी०, 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्चय की रूपरेखा, नई दिल्ली।
5. शुक्ला, संजीव, भारतीय आधुनिक शिक्षा—अप्रैल 2011, एन०सी०इ०आर०टी० नई दिल्ली।